

## मौद्रकि नीतिकी द्वमिसकि समीक्षा : रजिस्ट्र बैंक ने चार साल में पहली बार की रेपो दर में वृद्धि

### संदर्भ

रजिस्ट्र बैंक ने महँगाई बढ़ने की चति के चलते मुख्य नीतिगत दर रेपो दर में 0.25 प्रतशित की वृद्धिकर इसे 6.25 प्रतशित कर दिया जसिसे बैंक करज महँगा हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पछिले कुछ महीनों के दौरान कच्चे तेल के दाम बढ़ने से महँगाई को लेकर चति बढ़ी है। रजिस्ट्र बैंक ने पछिले चार साल में पहली बार रेपो दर में वृद्धिकी है।

### प्रमुख बातु

- मौद्रकि नीतिसमतिके अनुसार, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारत खुदरा मुद्रासफीतिअपरैल में तेज़ी से बढ़कर 4.6 प्रतशित पर पहुंच गई। इस दौरान खाद्य तथा ईधन को छोड़कर अन्य समूहों में तीव्र वृद्धिका इसमें अधिक योगदान रहा।
- नीतिगत दर रेपो में 0.25 प्रतशित की वृद्धिकर इसे 6.25 प्रतशित कर दिया गया है जसिसे बैंक करज महँगा हो सकता है।
- रविरस रेपो दर 6 प्रतशित तथा बैंक दर 6.50 प्रतशित है।
- जनवरी 2014 के बाद पहली बार रेपो दर में वृद्धिकी गई है।
- समीक्षा में चालू वित्त वर्ष के लयि आरथकि वकिस दर का अनुमान 7.4 प्रतशित पर पूरवत बनाए रखा गया है।
- चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के लयि खुदरा मुद्रासफीतिअनुमान को बढ़ाकर 4.8-4.9 प्रतशित कर दिया गया है, जबकि विर्ष की दूसरी छमाही के लयि इसे 4.7 प्रतशित रखा गया है।
- रजिस्ट्र बैंक के मुद्रासफीतिके इस अनुमान में केंद्र सरकार के करमचारियों को मलिने वाले बढ़े महँगाई भत्ते का असर भी शामलि है।
- पछिले दो माह में कच्चे तेल की कीमतों में 12 प्रतशित की तेज़ी आई है।
- भू-राजनीतिक जोखमि, वित्तीय बाजार में उतार-चढ़ाव, व्यापार संरक्षणवाद का घरेलू वृद्धिपर प्रभाव पड़ेगा।

### मौद्रकि नीतिसमति

मौद्रकि नीतिसमति(Monetary Policy Committee-MPC) भारत सरकार द्वारा गठति एक समतिहै जसिका गठन ब्याज दर नियंत्रण को अधिक उपयोगी एवं प्रारद्धशी बनाने के लयि 27 जून, 2016 को कया गया था। भारतीय रजिस्ट्र बैंक अधनियम में संशोधन करते हुए भारत में नीतिनियमाण को नवगठति मौद्रकि नीतिसमति(MPC) को सौंप दिया गया है।

- वित्त अधनियम 2016 के द्वारा रजिस्ट्र बैंक ऑफ इंडिया अधनियम 1934 (आरबीआई अधनियम) में संशोधन कया गया, ताकि मौद्रकि नीतिसमति को वैधानिक और संस्थागत रूप प्रदान कया जा सके।
- आरबीआई एकट के प्रावधानों के अनुसार, मौद्रकि नीतिसमति के छह सदस्यों में से तीन सदस्य आरबीआई से होते हैं और अन्य तीन सदस्यों की नियुक्तिकेंद्रीय बैंक करता है।
- रजिस्ट्र बैंक के गवर्नर इस समतिके पदेन अध्यक्ष हैं, जबकि भारतीय रजिस्ट्र बैंक के डिप्टी गवर्नर मौद्रकि नीतिसमति के प्रभारी के तौर पर काम करते हैं।

### उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (consumer price index या CPI) घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई वस्तुओं एवं सेवाओं (goods and services) के औसत मूल्य को मापने वाला एक सूचकांक है।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना वस्तुओं एवं सेवाओं के एक मानक समूह के औसत मूल्य की गणना करके की जाती है।
- वस्तुओं एवं सेवाओं का यह मानक समूह एक औसत शहरी उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाने वाली वस्तुओं का समूह होता है।

### रेपो दर

जैसा कहिम जानते हैं बैंकों को अपने काम-काज के लयि अक्सर बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। बैंक इसके लयि आरबीआई से अलपकाल के लयि करज मांगते हैं और इस करज पर रजिस्ट्र बैंक को उन्हें जसि दर से ब्याज देना पड़ता है, उसे ही रेपो दर कहते हैं। रेपो दर अधिक होने से मतलब है कि बैंक से मलिने वाले कई तरह के करज महँगे हो जाएँगे। जैसे कि होम लोन, वाहन लोन इत्यादी।

## रविर्स रेपो दर

यह रेपो दर के वपिरीत होती है। यह वह दर होती है जिसि पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मलिता है। रविर्स रेपो दर बाजारों में नकदी की तरलता को नयिंत्रित करने में काम आती है।

## मुद्रास्फीति

- जब मांग और आपूरति में असंतुलन पैदा होता है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। कीमतों में इस वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं।
- अत्यधिक मुद्रास्फीति अरथव्यवस्था के लिये हानकारक होती है, जबकि 2 से 3% की मुद्रास्फीति की दर अरथव्यवस्था के लिये ठीक होती है।
- मुद्रास्फीति भिख्यतः दो कारणों से होती है- मांग कारक और मूल्य वृद्धिकारक से।
- मुद्रास्फीति के कारण अरथव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में मंदी आ जाती है।
- मुद्रास्फीति का मापन तीन प्रकार से किया जाता है- थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एवं राष्ट्रीय आय वचिलन वधि से।

## रेपो दर और मुद्रास्फीति में संबंध

- रेपो दर कम होने से बैंकों के लिये रजिस्ट्रेशन बैंक से कर्ज लेना सस्ता हो जाता है और तभी बैंक ब्याज दरों में भी कटौती करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा रकम कर्ज के तौर पर दी जा सके। रेपो दर में वृद्धि होने पर सभी प्रकार के कर्ज महँगे हो जाते हैं।
- मुद्रास्फीति बढ़ने का एक मतलब यह भी है कि विस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि के कारण, बढ़ी हुई करय शक्ति के बावजूद लोग पहले की तुलना में वर्तमान में कम वस्तु एवं सेवाओं का उपभोग कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आरबीआई का कार्य यह है कि वह बढ़ती हुई मुद्रास्फीति पर नयिंत्रण रखने के लिये बाज़ार से पैसे को अपनी तरफ खींच ले। अतः आरबीआई रेपो दर में बढ़ोतरी कर देता है ताकि बैंकों के लिये कर्ज लेना महँगा हो जाए और वे अपने बैंक दरों को बढ़ा दें तथा लोग कर्ज न ले सकें।

## नष्टिकरण

जीडीपी में शानदार वृद्धि, खुदरा महँगाई दर का नचिले स्तर पर होना, मजबूत GST संग्रह और सकारात्मक निविशक वचिलरों के साथ मौद्रिकि नीति इस बात की पुष्टि करती है कि आरथिक गतिविधियों में उछाल आ रहा है।

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/rbi-tweaks-norms-to-boost-affordable-housing-lending>